Daily Current Affairs 08 September 2022

Index

- नीति आयोग: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात पोषण अभियान योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य
- यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारतीय शहर
- गडकरी बेंगलुरु में सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे
- डिजिटल इंडिया मिशन: ई-अभियोजन पोर्टल के उपयोग में उत्तर प्रदेश अव्वल
- यूपी के फर्रुखाबाद में 'जेल का खाना' को मिली 5-स्टार FSSAI रेटिंग
- मोहला-मानपुर-अम्बाग चौकी छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बना
- भारत बायोटेक द्वारा भारत की पहली इंट्रानैसल COVID वैक्सीन को DCGI की स्वीकृति मिली
- नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 7 सितंबर

Important News: National

1. नीति आयोग: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात पोषण अभियान योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य

चर्चा में क्यों:

- नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र के प्रमुख पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के मामले में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात को बड़े राज्यों में शीर्ष तीन राज्यों के रूप में स्थान दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- नीति आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, छोटे राज्यों में सिक्किम का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा हैं।
- महामारी के समय में पोषण अभियान शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, 19 बड़े राज्यों में से 12 राज्यों का कार्यान्वयन स्कोर 70 प्रतिशत से अधिक हैं।
- नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में शीर्ष स्थान पर हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब और बिहार पोशन अभियान के समग्र कार्यान्वयन के मामले में बड़े राज्यों में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12-23 महीने की उम्र के 75 प्रतिशत से अधिक बच्चे पूरी तरह से प्रतिरक्षित थे, जबकि 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25 प्रतिशत से कम पूरी तरह से प्रतिरक्षित बच्चे थे।
- रिपोर्ट के अनुसार, 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 प्रतिशत से अधिक (0-59 महीने) डायरिया के मामलों में ओआरएस के साथ इलाज किया गया हैं, जबकि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ओआरएस के साथ 25 प्रतिशत से कम बाल डायरिया के मामलों का इलाज किया गया है।
- नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, पोषण अभियान के तहत कुल फंड का उपयोग कम किया गया है, 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत से कम फंड का उपयोग किया गया है।

- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कन्वर्जेंस एक्शन प्लान (सीएपी) का संचालन करना आवश्यक हैं जिसकी सहायता से अभिसरण परिणाम-उन्मुख हो तथा सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।

स्रोत: नवभारत टाइम्स

2. यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारतीय शहर

चर्चा में क्यों:

- भारत के तीन शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया हैं, जिसमें केरल के दो शहर त्रिशूर और नीलांबुर तथा तेलंगाना का वारंगल जिला शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

- नीलांबुर केरल का एक प्रसिद्ध इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन है, तथा यहां की अधिकांश आबादी कृषि और संबद्ध उद्योगों पर निर्भर है।
- त्रिशूर, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं, तथा इसको केरल की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, त्रिशूर विशेष रूप से सोने की कला और आभूषण उद्योग के रूप में भी जाना जाता है।
- वारंगल तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है, तथा यह राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है।
- वारंगल के शामिल होने से इस सूचि में तेलंगाना के 2 जिले सूचि में शामिल हो गए हैं इससे पूर्व मुलुगु जिले के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था।
- इस वर्ष यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की इस सूची में यूक्रेन की राजधानी कीव, दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन और यूएई शहर शारजाह को भी शामिल किया गया है।
- वर्ष 2022 में भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है।
- वर्ष 2013 में शुरू किया गया, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज (जीएनएलसी) एक अंतरराष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है।
- यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज का उद्देश्य अन्य शहरों के साथ विचारों और कलाओं को साझा करके सभी सीखने वाले शहरों का विकास सुनिश्चित करना है।
- यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज सूची में अभी तक 76 देशों के 294 शहर को शामिल किया गया हैं।

स्रोत: द हिंदू

3. गडकरी बेंगलुरु में सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे

चर्चा में क्यों:

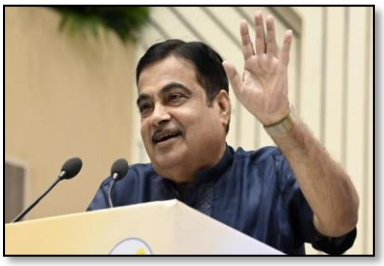

- केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी द्वारा बेंगलुरु में 'मंथन' का उद्घाटन किया जायेगा।

प्रमुख बिंदु:

- सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मंथन का आयोजन किया गया है, जो तीन दिवसीय आमंत्रण सम्मेलन सह सार्वजनिक एक्सपो है।
- मंथन का उद्देश्य सड़कों, परिवहन और रसद क्षेत्र में कई मुद्दों और अवसरों पर चर्चा करना और राज्य के साथ जुड़ना है।
- मंथन की थीम 'आइडियाज टू एक्शन: टुवर्ड्स ए स्मार्ट, सस्टेनेबल, रोड इन्फ्रा, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम' हैं।
- इस आयोजन में, कई राज्य मंत्री, पीडब्ल्यूडी, परिवहन और उद्योग मंत्रालयों के विभागों और इन मंत्रालयों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा भाग लिया जायेगा।
- आयोजन की चर्चा तीन क्षेत्रों में की जाएगी जिसमें शामिल हैं-
- प्रथम सड़कों पर, सड़क विकास, नई सामग्री, प्रौद्योगिकी और सड़क सुरक्षा को कवर करना।
- दूसरे चरण में, परिवहन क्षेत्र, जिसमें ईवी और वाहन सुरक्षा शामिल हैं।
- तीसरे चरण में, वैकल्पिक और भविष्य की गतिशीलता, जिसमें रोपवे, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, पर्वतमाला और डिजिटल हस्तक्षेप शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम के दौरान परिवहन विकास परिषद की 41वीं बैठक भी आयोजित की जाएगी।
- मंथन इवेंट के दौरान नेक्स्ट-जेन मोबाइल ऐप एम परिवहन भी लॉन्च किया जाएगा।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

Important News: State

4. डिजिटल इंडिया मिशन: ई-अभियोजन पोर्टल के उपयोग में उत्तर प्रदेश अव्वल

चर्चा में क्यों:

- उत्तर प्रदेश, 9.12 मिलियन मामलों के साथ, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई-अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु:

- अगस्त के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश 2.31 मिलियन के साथ बिहार तथा गुजरात के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
- दो वर्ष पूर्व राज्यों द्वारा शुरू किया गया ई-अभियोजन पोर्टल जघन्य अपराधों में आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने में अदालतों और अभियोजन प्रणाली की मदद करने के लिए गृह मंत्रालय, आईटी और कानून मंत्रालयों की एक पहल है।
- पोर्टल इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के तहत पुलिस विभाग और अभियोजन निदेशालय के बीच ई-संचार प्रदान करता है जो अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच डेटा के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराध और साइबर अपराध से संबंधित मामलों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की घटनाओं से संबंधित मामलों में गिरफ्तार लोगों की सजा और अवैध आग्नेयास्त्रों की जब्ती में भी शीर्ष पर है।
- उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 100 दिनों में, विभाग का लक्ष्य POCSO अधिनियम के तहत 1,000 दोषियों की सजा और महिलाओं के खिलाफ अपराध हासिल करना है।
- सरकार द्वारा ई-अभियोजन मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है जो अदालतों में अभियोजकों की सभी न्यायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को शामिल करेगा।
- ई-अभियोजन पोर्टल का उद्देश्य महत्वपूर्ण मामलों के अभियोजन में निरंतर प्रगति को बनाए रखने के लिए सभी जिलों में अधिकारियों की प्रगति की निगरानी करना और इस प्रकार लोगों में विश्वास की भावना पैदा करना है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

5. यूपी के फर्रुखाबाद में 'जेल का खाना' को मिली 5-स्टार FSSAI रेटिंग

चर्चा में क्यों:

- उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा पांच सितारा रेटिंग प्रदान की गयी है।

प्रमुख बिंदु:

- एफएसएसएआई द्वारा पैनल में शामिल एक तीसरे पक्ष के ऑडिट द्वारा जेल को पांच सितारा 'ईट राइट सर्टिफिकेट' प्रदान किया गया हैं।
- यह भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की मान्यता है, जिसका अर्थ है कि जेल में कैदियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ भोजन प्रदान किया जा रहा है।
- एफएसएसएआई की "ईट राइट" मान्यता के अनुसार फर्रुखाबाद जेल में 1,100 कैदियों को स्वच्छ और स्वस्थ भोजन प्रदान किया जाता हैं।
- जेल प्रशासन द्वारा बड़ी-बड़ी रोटी बनाने वाली मशीनें, आटा गूंथने की मशीन और सब्जियों के लिए मशीन-कटर लगाकर इसका आधुनिकीकरण किया है, इससे पूर्व रोटियां, सब्जी और दाल तैयार करने में बंदियों की मदद ली जाती थी।
- इससे पूर्व मैनुअल प्रक्रिया होने के कारण इसमें काफी समय लगता था तथा प्रत्येक पाली के लिए भोजन तैयार करने के लिए लगभग 50 कैदियों को काम में लगाया जाता था।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

6. मोहला-मानपुर-अम्बाग चौकी छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बना

चर्चा में क्यों:

- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के 29वें जिले के रूप में नवगठित जिले मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी का उद्घाटन किया गया हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जिले के मानचित्र का भी अनावरण किया गया हैं।

- नवगठित जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी को राजनांदगांव जिले से अलग कर एक नई प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाया गया है।
- नया जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी दुर्ग संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया हैं।
- वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी एस जयवर्धन को नवगठित जिले का पहला कलेक्टर बनाया गया है, जबकि येदुवल्ली अक्षय कुमार नवगठित जिले के पहले एसपी होंगे।
- नवगठित जिले में तीन तहसीलो - अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर तथा तीन विकास खंड तथा जनपद पंचायत – अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर को शामिल किया गया हैं।
- नए जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2 लाख 14 हजार 667 हेक्टेयर है, तथा यहाँ की कुल जनसंख्या 2 लाख 83 हजार 947 है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 1 लाख 79 हजार 662 है, जो जिले की कुल जनसंख्या का 63.27 प्रतिशत है।
- जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या 13, पटवारी हलका की कुल संख्या 89, तथा ग्राम पंचायत की संख्या 185 है।
- जिले में कुल पुलिस थानों की संख्या 9, विधानसभा क्षेत्र की 2 तथा कुल मतदान केंद्र 497 हैं।
- नवगठित जिले मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में कुल गांवों की संख्या 499 है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

Important News: Health

7. भारत बायोटेक द्वारा भारत की पहली इंट्रानैसल COVID वैक्सीन को DCGI की स्वीकृति मिली

चर्चा में क्यों:

- भारत बायोटेक द्वारा भारत के पहले इंट्रानैसल कोविड वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए इंजेक्शन के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी है।

प्रुमख बिंदु:

- इंट्रानैसल COVID वैक्सीन COVID-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैं।

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा वैक्सीन को COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए एक 'बिग बूस्ट' करार दिया गया हैं।
- भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (बीबीआईएल), वैक्सीन नवाचार में एक वैश्विक कंपनी और संक्रामक रोगों के लिए टीकों के विकासकर्ता है।
- BBIL ने घोषणा की कि इंट्रानैसल COVID वैक्सीन (BBV154) के विकास को आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है।
- iNCOVACC, एक पूर्व-संलयन स्थिर स्पाइक प्रोटीन के साथ एक पुनः संयोजक प्रतिकृति-कमी वाले एडेनोवायरस वेक्टरेड वैक्सीन है।
- इस टीके का मूल्यांकन सफल परिणामों के साथ नैदानिक परीक्षण चरण I, II और III में किया गया था।
- वैक्सीन को नाक की बूंदों के माध्यम से इंट्रानैसल डिलीवरी की अनुमति देने के लिए तैयार किया गया हैं।
- इंट्रानैसल वैक्सीन को निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लागत प्रभावी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

Important News: Days

8. नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 7 सितंबर

चर्चा में क्यों:

- वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 07 सितंबर को विश्व स्तर पर नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सामूहिक जवाबदेही और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए वायु प्रदूषण की सीमा पार प्रकृति पर केंद्रित है।

- यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
- इस वर्ष का विषय "द एयर वी शेयर" वायु प्रदूषण की सीमा पार प्रकृति पर केंद्रित है, जो सामूहिक जवाबदेही और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देता है।
- अपने 74 वें सत्र के दौरान, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर, 2019 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया था।
- यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को की गयी थी तथा इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित हैं।
- यूएनईपी के संस्थापक मौरिस स्ट्रॉन्ग हैं, तथा वर्तमान यूएनईपी प्रमुख इंगर एंडरसन हैं।

स्रोत: दैनिक भास्कर